Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE)

Monthly Summary for the month of June, 2019

Important events for the month of June, 2019 are as follows:

(a) A Delegation from Singapore, led by Singapore's Minister of Education, visited New Delhi from 6-7 June 2019. A Minister-level meeting was organized by MSDE on 6th June 2019 to interact with the delegation from Singapore. As skilling in Singapore comes under the purview of the Education Ministry, the objective of the visit of the Minister for Education and his delegation was to understand the skills ecosystem in India and explore possible opportunities to partner Indian skills stakeholders.

(b) A technical meeting on the Indo-German Cooperation in Vocational Education Training was held between MSDE and German Delegation at Kaushal Bhawan, New Delhi on 14th June 2019.

(c) First meeting of Joint Steering Committee for India-UK Cooperation in the field of Skill Development was held on 17th June 2019 at India Habitat Centre, New Delhi.

(d) The fee for SC/ST candidates joining vocational training under Jan Shikshan Sansthan Scheme (JSS) has been waived off with effect from 4thJune, 2019.

(e) With an objective to ensure that assessment and certification of Jan Shikshan Sansthan Scheme (JSS) beneficiaries is standardized with transparency, accountability, uniform across the board and lend credibility to JSS training and online certification, an evidence based Assessment and Certification Guidelines for JSS has been finalized by MSDE.

(f) To provide a unique ownable branding template for Jan Shikshan Sansthan (JSS), that is rooted in its Indian origins, a Branding Guidelines for the Jan Shikshan Sansthan has been finalized by MSDE.

(g) The claims of MSDE against the achievement of the Disbursement Linked Indicator (DLI)-5 were verified by Independent Verification Agency (IIM Indore) and the same has also been forwarded to the D/o Economic Affairs for unlocking funds amounting to USD 15,920,000/- from the World Bank against the said achievements.

(h) The second Inter-Ministerial Empowered Committee meeting in connection with 'Setting up of Indian Institute of Skills (IIS)' was held on 19th June 2019 at Shram Shakti Bhawan, New Delhi to discuss on the report of the sub-committee on the Empowered Committee.

(i) Under STRIVE (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement) project, State Apprenticeship Monitoring Cell (SAMC) for 06 States (Karnataka, Punjab, Assam, Rajasthan, Manipur, Meghalaya) approved and total funds of Rs. 3.52 Crore released to 08 States (where SAMC was already approved).

(j) MoUs have been signed between State Govt. of Nagaland, Puducherry and Govt. of India to implement the STRIVE project. Till date a total of 27 MoUs have been signed with various states/UTs. Tripartite agreements for 13 Industrial Training Institutes (ITIs) of Andhra Pradesh and 16 ITIs of Haryana were signed for implementation of STRIVE.

(k) Video Conferencing was held with 11 states to discuss the challenges pertaining to implementation of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) in all the States and solve any operational challenges faced by the State Skill Development Missions (SSDMs).

****

<u>कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई)</u>

जून, 2019 माह के लिए मासिक सारांश

<u>जून, 2019 माह की महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नानुसार है:</u>

(क) सिंगापुर के शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में सिंगापुर के एक प्रतिनिधि मंडल ने 6-7 जून 2019 को नई दिल्ली का दौरा किया। सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करने के लिए एमएसडीई द्वारा 6 जून, 2019 को मंत्री स्तर की एक बैठक आयोजित की गई थी। चूंकि सिंगापुर में कौशलीकरण शिक्षा मंत्री के कार्य क्षेत्र में आता है, अत: शिक्षा मंत्री और उसके प्रतिनिधि मंडल के दौरे का उद्देश्य भारत में कौशल ईकोसिस्टम को समझना और भारतीय कौशल हितधारकों के साथ भागीदारी करने के अवसरो की संभावना तलाश करना था।

(ख) व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण में भारत-जर्मन सहयोग पर एमएसडीई और जर्मन प्रतिनिधि मंडल के बीच एक तकनीकी बैठक 14 जून, 2019 को कौशल भवन नई दिल्ली में हुई थी।

(ग) कौशल विकास के क्षेत्र में भारत-यूके सहयोग के लिए संयुक्त संचालन समिति की पहली बैठक इंडिया हेबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 17 जून, 2019 को हुई थी।

(घ) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले अनु.जाति/अनु.जनजाति उम्मीदवारों के लिए शुल्क को 4 जून, 2019 से समाप्त कर दिया गया है।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि जन शिक्षण संस्थान स्कीम (जेएसएस) लाभार्थियों के आकलन और प्रमाणन पारदर्शी, उत्तरदायित्व, बोर्ड में समानता और जेएसएस प्रशिक्षण की साख बनाने और ऑनलाइन प्रमाणन के साथ मानकीकृत है, जेएसएस के लिए आकलन और प्रमाणन दिशा-निर्देश आधारित साक्ष्यों को एमएसडीई द्वारा अंतिम रूप दिया गया है।

(च) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) के लिए एक विशिष्ट स्वामित्व ब्रांडिंग टेम्पलेट, जो अपने भारतीय स्वरूप में विद्यमान है, उपलब्ध कराने के लिए जन शिक्षण संस्थान के लिए ब्रांडिंग दिशा-निर्देशों को एमएसडीई द्वारा अंतिम रूप दिया गया है।

(छ) संवितरण संबद्ध संकेतक (डीएलआई)- 5 की उपलब्धियों के लिए एमएसडीई के दावों का स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी (आईआईएम इंदौर) द्वारा सत्यापन कराया गया था और उक्त उपलब्धियों के लिए विश्व बैंक से 15,920,000/- अमरीकी डॉलर की धनराशि निर्मुक्त करने के लिए इसे आर्थिक कार्य विभाग को भी भेजा गया था।

(ज) भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) स्थापित करने के संबंध में अंतर मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति की दूसरी बैठक अधिकार प्राप्त समिति संबंधी उक्त समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 19 जून, 2019 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(झ) स्ट्राइव (औद्योगिक मूल्य वर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण) परियोजना के अंतर्गत 6 राज्यों (कर्नाटक, पंजाब, असम, राजस्थान, मणिपुर, मेघालय) के लिए राज्य शिक्षुता निगरानी प्रकोष्ठ (एसएएमसी) को अनुमोदित किया गया और 8 राज्यों (जहां एसएएमसी अनुमोदित किए जा चुके हैं) को 3.52 करोड़ रूपए की कुल राशि जारी की गई।

(ञ) स्ट्राइव परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए नागालैंड, पुद्दुचेरी की राज्य सरकारों और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अब तक कुल 27 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्ट्राइव के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश के 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और हरियाणा के 16 आईटीआई के लिए त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

(ट) सभी राज्यों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियों और राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) के समक्ष आने वाली प्रचालनात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए 11 राज्यों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग की गई।

******